Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी का नया लोगो और वेबसाइट की लॉन्च 3
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022' को दी मंज़ूरी 3
- राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी 5
- वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना 5
- हरियाणा और उज़्बेकिस्तान ने एफएफसी पर किये हस्ताक्षर 6
- हरियाणा के रेसलरों ने कॉमनवेल्थ खेलों में लगाई पदकों की झड़ी 6
- करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 7
- डिजिटल हरियाणा विधानसभा का उद्घाटन 8
- चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 15 लाख रुपए 9
- प्रधानमंत्री ने पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया 9
- हरियाणा में स्थापित हुई एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल 10
- हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित 10
- हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित 11
- हरियाणा सरकार ने 10 गाँवों को मिलाकर नई नगर परिषद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की 11
- मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंग्का सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया 'मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट' के निर्माण का शुभारंभ किया 12
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की सरसों की दो उन्नत किस्में 13
- हथनीकुंड डैम प्रोजेक्ट 14
- हालसा अध्यक्ष ने किया रेवाड़ी के एडीआर सेंटर का लोकार्पण 14
- हैफेड ने लॉन्च किया मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन 15
- फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल 'अमृता अस्पताल' का उद्घाटन 15
- हरियाणा की अंजू दहिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 16
- पुस्तक 'द गुरु: गुरुनानक की साखियाँ' का विमोचन 16
- नीरज चोपड़ा ने जीता लुसाने डायमंड लीग का खिताब 17
- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और हरियाणा के बीच हुआ समझौता 17
- हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड-2021 की घोषणा की 18

नोट :

हरियाणा

मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी का नया लोगो और वेबसाइट की लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

30 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) का पुन: डिज़ाइन किया गया लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हरियाणा को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एचएसआईआईडीसी की यह नई पहचान अभिनव, आधुनिक और पेशेवर है। एचएसआईआईडीसी उन उद्यमियों को सेवाएँ प्रदान करेगा, जो व्यवसायों को विकसित और विस्तार करना चाहते हैं।
- एचएसआईआईडीसी की नई वेबसाइट और ब्रांड पहचान इसकी मार्केट लीडिंग पोजीशन को बेहतर ढंग से दर्शाती है और ग्राहकों के लिये सेवाओं के व्यापक चक्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। डिजिटल और भौतिक माध्यमों पर सुगमता से कार्य करने के लिये डिज़ाइन किया गया नया लोगो प्रेरणा, नवाचार और उद्यमिता की भावना पैदा करता है।
- एचएसआईआईडीसी के नए लोगो में तितली का रूपक एक कोकून में रहने की प्रक्रिया से गुज़रने की तरह एक विचार से एक सफल व्यवसाय में परिवर्तन का प्रतीक है। चार पंख उद्योग 0 को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यह लोगो दर्शाता है कि कैसे एचएसआईआईडीसी कंपनियों को व्यवसाय की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।
- नव-डिज़ाइन वेबसाइट में सहज उपयोगकर्त्ता अनुभव प्रदान करने के लिये लेआउट तैयार किया गया है। यह वेबसाइट एचएसआईआईडीसी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर भी प्रकाश डालती है और पुनर्परिभाषित दृष्टिकोण की एक झलक दर्शाती है।
- एचएसआईआईडीसी हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये हरियाणा सरकार की नोडल एजेंसी है। निगम ने 6 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (मानेसर, फरीदाबाद, बावल, रोहतक, सोहना और खरखौदा) विकसित किये हैं। इसके अलावा, 28 इंडस्ट्रियल एस्टेट और थीम पार्क (राई, साहा और बड़ी में फूड पार्क, आईएमटी मानेसर और राई में प्रौद्योगिकी पार्क व बहादुरगढ़ में फुटवियर पार्क) भी स्थापित किये गए हैं, जहाँ 16000 से अधिक इकाइयाँ काम कर रही हैं।
- औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास में 55 वर्षों की बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ एचएसआईआईडीसी ने कई प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाई है, जिसमें ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मिक्सड लैंड यूज़ डेवलपमेंट और नांगल चौधरी ज़िला महेंद्रगढ़ में 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना शामिल हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022' को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022' को मंज़ूरी प्रदान की गई। यह नीति मुख्य शहरीकरण और औद्योगीकरण के उद्देश्यों के लिये लैंडबैंक बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख बिंदु

- नीति में विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और समयबद्ध तरीके से भूमि विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

नोट :

- हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास सहित नियोजित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना और उक्त विकास में भागीदार बनने के इच्छुक भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त करना है।
- इस नीति का उद्देश्य हरियाणा अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध के प्रावधानों के अनियमित विकास अधिनियम, 1963 के तहत राज्य सरकार द्वारा पब्लिशड डेवलपमेंट प्लान के निर्धारित क्षेत्र के भीतर एक सेक्टर या उसके हिस्से के विकास के लिये भूमि की पूलिंग हेतु एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र विकसित करना है।
- इस नीति का एक अन्य उद्देश्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि (रॉ लैंड) की लागत से जोड़कर भूमि मालिक को अधिकतम लाभ प्रदान करना है।
- इस नीति के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पब्लिशड डेवलपमेंट प्लान में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रों के मामले में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढाँचे का विकास करेगा।
- इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) इस नीति के तहत हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक बुनियादी ढाँचे या संस्थागत उद्देश्यों के लिये विकास कार्य करेगा।
- इस नीति के तहत एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के लिये उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा राज्य सरकार द्वारा किसी भी विभाग या किसी बोर्ड, निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठन को किसी भी निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिये अधिकृत किया जा सकता है।
- यह नीति निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिये परियोजना हेतु भूमि की पेशकश करने वाले भूमि मालिकों पर लागू होगी। यह नीति उन एग्रीगेटर पर लागू होगी, जो निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिये परियोजना हेतु भूमि की पेशकश करने के लिये कई भूमि मालिकों के साथ समझौते के तहत भूमि एकत्र करते हैं।
- यह नीति विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुरूप भूमि के लिये लागू होगी। साथ ही, यह नीति हरियाणा में किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में भी लागू होगी, जहाँ विकास का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा या औद्योगिक विकास हो।
- डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा भू-स्वामियों को एक भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जो ट्रेड या मोर्टगेज रखा जा सकता है।
- इस नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक, या तो सीधे या एक एग्रीगेटर के माध्यम से प्रकाशन में निर्दिष्ट अवधि, जोकि 60 दिनों से कम नहीं होगी, के भीतर विकास उद्देश्य के लिये परियोजना हेतु भूमि की पेशकश करने के लिये आवेदन जमा कर सकता है। इस अवधि को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यह 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं होगा।
- भूमि मालिक परियोजना के लिये प्रस्तावित भूमि के विवरण के साथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन की वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। मैन्युअल रूप से जमा किये गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
- विकास परियोजना के लिये योगदान करने वाले प्रत्येक भूस्वामी को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा।
- परियोजना की कुल लागत सभी भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अविकसित भूमि के मूल्य, विकास की लागत, अंतरिम वार्षिक सहायता और प्रशासनिक शुल्क का योग होगा।
- भूमि मालिक, सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से, निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिये परियोजना हेतु राज्य सरकार के ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपने स्वामित्व वाली भूमि की पेशकश करने के लिये स्वतंत्र होगा। इस स्थिति में उक्त प्रस्ताव पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 6 फरवरी, 2017 की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- यदि एग्रीगेटर के माध्यम से भूमि की पेशकश की जाती है, तो एग्रीगेटर भूस्वामियों और एग्रीगेटर के बीच सहमति के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि पारिश्रमिक 0.5 प्रतिशत से कम न हो।

नोट :

राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी

चर्चा में क्यों ?

30 जुलाई, 2022 को अंबाला से नारनौल तक बनाए गए नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-152डी को आमजन के लिये खोल दिया गया, ताकि इसका परीक्षण किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी परियोजना अंबाला से जयपुर तक की यात्रा के समय को 4 से 5 घंटे कम कर देगी। इससे एनसीआर के ट्रैफिक का मेजर डायवर्जन होगा, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी।
- साथ ही, यह जयपुर हाईवे पर अंबाला से कोटपुतली तक सबसे छोटा, सबसे तेज़ और सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा तथा पूरे हरियाणा के चौतरफा औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की गति को तेज़ करेगा।
- भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-152डी 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्स ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जो कुरुक्षेत्र ज़िले के इस्माईलाबाद (गंगहेड़ी) से नारनौल तक कुल लगभग 227 किमी. लंबा है।
- यह राजमार्ग अंबाला-कोटपुतली कॉरिडोर का भाग है, जो हरियाणा के 8 विभिन्न ज़िलों- कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लगभग 112 गाँवों से होकर गुज़रता है। यह आगे नारनौल बाईपास तथा फिर एनएच-148बी से जुड़ा है, जो कोटपुतली के पास पनियाला मोड़ पर दिल्ली-जयपुर राजमार्ग से मिलता है।
- यह पूरा कॉरिडोर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और क्लोज टोलिंग सिस्टम से परिपूर्ण है। इसमें प्रवेश एवं निकासी के लिये कुल 16 विभिन्न स्थानों पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है तथा हाईवे पर होने वाली हर घटना पर कंट्रोल सेंटर के द्वारा एटीएमएस के माध्यम से पूर्ण निगरानी रखी जाएगी।
- लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना में छः जगहों पर विश्वस्तरीय वे साईड एमेनिटीज का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर लोगों के लिये टॉयलेट फेसिलिटी, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप, कायोस्क रेस्टोरेंट, ढाबा, चिल्ड्रेन पार्क, ट्रक एवं ट्रेलर पार्किंग इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही, परियोजना में 16 स्थानों पर इंटरचेंज, 2 मुख्य टोल प्लाजा एवं 8 आरओबी का भी प्रावधान किया गया है।
- इस परियोजना में लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का मुआवज़ा किसानों को वितरित किया गया है तथा इसके सिविल निर्माण कार्य पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत आई है।
- उपमुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को नया आयाम देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक जो निवेशक अपने उद्योग एनसीआर आदि क्षेत्र में लगाने को वरीयता देते थे, वे अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले ज़िलों में भी उद्योग लगाने को उत्सुक होंगे।
- यह राजमार्ग हाईस्पीड एक्सिस कंट्रोल्ड के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें धीमी गति वाले वाहनों यथा मोटरसाईकिल एवं अन्य दोपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों, गैर-मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर, बहुधुरीय हाइड्रॉलिक ट्रेलर वाहनों, क्वाड्री साईकिल इत्यादि वर्जित किये गए हैं।

वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिये वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक दिसंबर, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
- यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च, 2019 को निगम को भुगतान के लिये बकाया है। योजना 31 मार्च, 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी।
- ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिये पात्र होगी।
- छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे।

हरियाणा और उज़्बेकिस्तान ने एफएफसी पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में हरियाणा और उज़्बेकिस्तान ने परस्पर सहयोग एवं द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन (एफएफसी) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार की ओर से एफएफसी पर विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी तथा उज़्बेकिस्तान गणराज्य के फरगना क्षेत्र के उप-राज्यपाल इकबोलजोन एर्गाशेव द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- यह एफएफसी ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और अनुसंधान, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों के माध्यम से फरगना और हरियाणा के मध्य परस्पर सहयोग बनाने में मदद करेगा।
- इस अवसर पर योगेंद्र चौधरी ने कहा कि हरियाणा को ऑटोमोबाइल, शिक्षा, कौशल विकास, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख और अग्रणी राज्य बनाने के लिये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विज़न को साकार करने और लागू करने में फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, यह आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये दोनों क्षेत्रों के बीच एक्सचेंज कार्यक्रमों को सुगम बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैश्विक स्तर पर हरियाणा की पहचान बनाने और निवेशकों के लिये हरियाणा को पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। विदेश सहयोग विभाग अपने 'गो-ग्लोबल एप्रोच' के माध्यम से विदेशों के साथ विभिन्न स्तरों पर परस्पर समझ और सहयोग स्थापित कर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये निरंतर कार्य कर रहा है।

हरियाणा के रेसलरों ने कॉमनवेल्थ खेलों में लगाई पदकों की झड़ी

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG-2022) खेलों में हरियाणा के 5 रेसलरों ने कुश्ती में देश को 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक दिलाया।

मुख्य बिंदु

- सर्वप्रथम हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में कनाडा के लैचलन मैकनील को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

नोट :

- यह कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पूनिया का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक और लगातार तीसरा पदक है। कॉमनवेल्थ गेम्स-2014 में रजत पदक जीतने वाले पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2018 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था।
- रेसलिंग में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक महिला पहलवान साक्षी मलिक ने महिलाओं के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज को हराकर दिलाया।
- कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी मलिक का यह पहला स्वर्ण पदक तथा तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स-2014 में रजत पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स-2018 में कांस्य पदक जीता था।
- रेसलिंग में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक पहलवान दीपक पूनिया ने दिलाया। उन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह दीपक पूनिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक है।
- 21 वर्षीय महिला पहलवान अंशू मलिक महिलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नाइजीरिया की ओदुनायो फोलासादे अदेकुओरोए से हार गईं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा, हालाँकि अंशु मलिक ने ही कुश्ती में भारत के पदकों का खाता खोला था।
- अंशु मलिक ने 2016 में एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2016 में ही विश्व कैडिट चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2017 में विश्व खेल स्कूल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2017 में एशिया कैडिट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2017 में ही एथेंस में विश्व कैडिट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2018 में एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक, विश्व सब जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2019 में एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।
- हरियाणा के पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कुश्ती में भारत को पाँचवा पदक दिलाया। मोहित ने 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक मैच में जमैका के आरोन जॉनसन को हराकर कांस्य पदक जीता।

करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

6 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र में प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटरवाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से अच्छे चालक मिलेंगे व सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
- गौरतलब है कि इस संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने ही 29 मार्च, 2018 को किया था। करनाल में इस संस्थान को खोलने की घोषणा भी उन्होंने ही 14 दिसंबर, 2016 को की थी।
- लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ भूमि पर स्थापित यह सेंटर होंडा मोटर स्कूटर इंडिया लिमिटिड के सहयोग से स्थापित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार इस संस्थान में ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटरीकृत प्रणाली से युक्त क्लास रूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बनाए गए हैं।
- यहाँ दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, लाइट मोटर तथा भारी वाहनों के चालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। परीक्षण ट्रैक पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिये इस केंद्र में एक स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी होगा।
- यह संस्थान पूरी तरह से स्वचालित होगा और इसकी कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सेंटर में दूर के छात्रों के लिये छात्रावास भी बनाया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक सड़क दुर्घटनाएँ चालकों के पास कौशल और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। इसलिये चालक बनने के इच्छुक युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
- राज्य में चालकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के लिये राज्यभर में स्वचालित चालक प्रशिक्षण संस्थान व क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएँगे। इसके तहत कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में आधुनिक सुविधाओं तथा बुनियादी ढाँचे से लैस तीन चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किये गए हैं। अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसे मूल उपकरण निर्माता कंपनियाँ इन तीनों परियोजनाओं में भागीदार हैं।

नोट :

- इनके अलावा 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। इनमें ज़िला भिवानी में कालूवास, नूंह में छपेड़ा, रेवाड़ी में जयसिंहपुर खेड़ा, जींद में पेगा, सोनीपत में मुरथल, यमुनानगर में औरंगाबाद, पलवल में बहिन और ज़िला फरीदाबाद में खेड़ी गुजरां शामिल हैं। ज़िला गुरुग्राम में क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
- इन संस्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिये प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष खुद को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सेंटरों की स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवकों को देश-विदेश में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें लगभग 5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हरियाणा राज्य 13वें स्थान पर है। सड़क सुरक्षा के सभी कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग, हरियाणा को लीड एजेंसी घोषित किया गया है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारणों का सर्वेक्षण करके और उनके कारणों को सुधार कर राज्य में हो रही इन दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाना है। सड़क सुरक्षा एक बहुआयामी विषय है। इसमें केवल मात्र सरकार की ही भूमिका नहीं है, बल्कि जनता, गैर-सरकारी संस्थाओं और उद्योगों को भी आगे आना होगा, ताकि एक सुरक्षित सड़क तंत्र स्थापित किया जा सके।

डिजिटल हरियाणा विधानसभा का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का तथा पहली बार टैबलेट पर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए - नेवा) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा डिजिटल होने वाली देश की तीसरी विधानसभा है। अब इसका सारा काम ई-विधानसभा के माध्यम से होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इसके अलावा केंद्र सरकार से प्राप्त 150 में से 100 पुरस्कार डिजिटल क्षेत्र में ही प्राप्त हुए हैं।
- उद्घाटन सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप्लिकेशन के माध्यम से विधानसभा के सदस्य प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, विधानसभा के ऑडियो और वीडियो का ट्रैक रख सकते हैं। विधायक इस एप्लिकेशन का उपयोग न केवल मोबाइल पर बल्कि कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि नेवा एप्लिकेशन सिर्फ विधायकों के लिये बनाई गई है। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जाता है, लेकिन बाद में सभी को अपना गुप्त पासवर्ड बनाना होगा और सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होगा।
- उन्होंने कहा कि इसके अंदर विधानसभा के कार्यों के साथ-साथ क्षेत्र के विकास की जानकारी भी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक यह जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, उनके क्षेत्र में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है। यह जानकारी आम जनता भी विधायकों के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकेगी।
- विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ई-विधानसभा के गठन से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटाइज करने का कार्य किया है।
- उन्होंने कहा कि विधानसभा के पेपरलेस होने से सालाना साढ़े पाँच करोड़ रुपए की बचत होगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिये भी लाभदायक होगी।

नोट :

चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 15 लाख रुपए

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में ओलंपिक की तर्ज़ पर अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लाए गए अभिनंदन प्रस्ताव के पारित होने के बाद यह घोषणा की। गौरतलब है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिये अभिनंदन प्रस्ताव रखा था।
- खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश का एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहा है, उसे 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को पहली बार 15 लाख रुपए इनाम दिया था।
- खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए कुल मेडल में से लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की रही।
- खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेता को 1.50 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए का पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी (2जी) के इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- संयंत्र का लोकार्पण देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा वर्षों से उठाए गए कदमों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। यह ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिये प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा 2जी एथेनॉल प्लांट का निर्माण करीब 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है और यह पानीपत रिफाइनरी के करीब स्थित है।
- अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित, यह परियोजना सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिये सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) का उपयोग करके भारत के 'कचरे से कंचन' (वेस्ट टू वेल्थ) के प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू करेगी।
- भारत सरकार के 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट (EBMS) के लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस संयंत्र से उत्पादित इथेनॉल को मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रित किया जाएगा।
- कृषि-फसल अवशेषों के लिये अंतिम उपयोग का सृजन होने से किसान सशक्त होंगे और उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह परियोजना इस संयंत्र के संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करेगी और चावल के भूसे को काटने, संभालने, भंडारण आदि के लिये आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोज़गार तैयार होंगे।
- परियोजना में कोई तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा। पराली (पराली) को जलाने में कमी लाकर, यह परियोजना ग्रीनहाउस गैसों को लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम कर देगी, जिसे देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों को हटाए जाने के बराबर समझा जा सकता है।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस आधुनिक संयंत्र की स्थापना से हरियाणा के किसानों के लिये पराली अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी, जहाँ चावल और गेहूँ बहुतायत में उगाए जाते हैं। इस प्लांट से दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में प्रदूषण कम होगा।

नोट :

हरियाणा में स्थापित हुई एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल

चर्चा में क्यों ?

11 अगस्त, 2022 को हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि बढ़ती डिजिटल दुनिया के साथ-साथ एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी 22 ज़िलों में 22 एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल (एएफआईसी) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि गत माह 1 जुलाई, 2022 को शुरू की गई एएफआईसी को स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों से 132 अनट्रेस मुकदमे इन्वेस्टीगेशन के लिये सौंपे गए हैं।
- गौरतलब है वर्तमान में एटीएम आम इंसान की ज़िंदगी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अपराधियों ने इसी महत्त्वपूर्ण हिस्से पर सेंध लगाने का काम किया है। कई बार ऐसे फाइनेंसियल फ्रॉड के मामलों में ज़िला पुलिस द्वारा अनट्रेस रिपोर्ट दे दी जाती है और आरोपी बच निकलते हैं।
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (राज्य अपराध शाखा) ओ.पी.सिंह ने इस समस्या को सुलझाने और दोबारा से अनट्रेस मुकदमों पर काम करने के लिये कड़े निर्देश दिये हैं। इसी अवधारणा के तहत हरियाणा में राज्य अपराध शाखा के अंतर्गत एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन सेल की शुरुआत की गई है, जिसमें ज़िलों के अनट्रेस मुकदमों को सुलझाने का बीड़ा उठाया गया है।
- अक्सर अनुसंधान में सबूतों के अभाव में आरोपी बच जाते है, लेकिन एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की स्थापना इन अपराधों के ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि आम जनता की मेहनत की कमाई को बचाया जा सके।
- वर्तमान में स्टेट क्राइम ब्रांच के अंतर्गत काम करने वाली सेल सभी अनट्रेस मुकदमों का बारीकी से अध्ययन कर रही है, ताकि इन मुकदमों को सुलझा कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके और आमजन में पुलिस की कार्रवाई एवं निष्ठा के प्रति विश्वास और गहरा हो सके।

हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस के चार कर्मियों को वर्ष 2022 में अपराध से जुड़े मामलों की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हुए 'जाँच में उत्कृष्टता'के लिये 'केंद्रीय गृह मंत्री पदक' हेतु चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये घोषित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के आठ-आठ कर्मचारी तथा शेष अन्य राज्यों के हैं।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले देश भर के 151 पुलिसकर्मियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत कुमार, महिला सब-इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब-इंस्पेक्टर योगेश कुमार और हेड कॉन्स्टेबल गोपाल चंद शामिल हैं।
- हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाँच में उत्कृष्टता के लिये चयनित हरियाणा पुलिस के चारों कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के माध्यम से वारदातों को सुलझाया गया।
- उल्लेखनीय है कि अपराध की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की गई थी।
- इसके तहत किसी भी अपराध की जाँच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा व काम से असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को यह मेडल दिया जाता है।

नोट :

- 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये पाँच पुलिस पदक शुरू किये थे। इसमें विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जाँच में उत्कृष्टता पदक शामिल हैं।

हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस के चार कर्मियों को वर्ष 2022 में अपराध से जुड़े मामलों की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हुए 'जाँच में उत्कृष्टता'के लिये 'केंद्रीय गृह मंत्री पदक' हेतु चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये घोषित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के आठ-आठ कर्मचारी तथा शेष अन्य राज्यों के हैं।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले देश भर के 151 पुलिसकर्मियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत कुमार, महिला सब-इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब-इंस्पेक्टर योगेश कुमार और हेड कॉन्स्टेबल गोपाल चंद शामिल हैं।
- हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाँच में उत्कृष्टता के लिये चयनित हरियाणा पुलिस के चारों कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के माध्यम से वारदातों को सुलझाया गया।
- उल्लेखनीय है कि अपराध की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की गई थी।
- इसके तहत किसी भी अपराध की जाँच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा व काम से असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को यह मेडल दिया जाता है।
- 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये पाँच पुलिस पदक शुरू किये थे। इसमें विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जाँच में उत्कृष्टता पदक शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ने 10 गाँवों को मिलाकर नई नगर परिषद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार ने पटौदी नगर पालिका तथा हेलीमंडी नगर पालिका (राजस्व संपदा जाटौली) तथा आसपास के 10 गाँवों को मिलाकर नगर परिषद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- जारी अधिसूचना के अनुसार गाँव नरहेड़ा, जनौला, रामपुर, छावन, मिल्कपुर, मिर्जापुर, मुबारकपुर, देवलावास, हेड़ाहेडी तथा खानपुर इस नए नगर परिषद, पटौदी-मंडी का हिस्सा होंगे।
- पटौदी-मंडी नगर परिषद बनाने पर पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि आखिरकार आजादी के 75 वर्ष बाद गुलामी के प्रतीक हेली शब्द से मुक्ति मिली है। लोगों का कहना था कि हेली एक अंग्रेज गवर्नर था। उसके नाम से नगर का नाम उचित नहीं है। अब नए नगर परिषद का गठन होने से यह विवाद समाप्त हो गया है।

नोट :

- नई सीमाओं की जानकारी उत्तर-बिंदु 'ए' जो कि नगरपालिका, हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली), ग्राम लुहारी तथा फरीदपुर का त्रि-मिलन है, से आरंभ होकर पूर्व की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की उतरी सीमा के साथ तथा ग्राम फरीदपुर, महचाना तथा खंडेवला की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'बी' तक होगी जो कि नगरपालिका, हेलीमंडी, ग्राम खंडेवला तथा रामपुर की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- इसके उपरांत बिंदु 'बी' से पूर्व दक्षिण की तरफ ग्राम रामपुर की उतरी सीमा के साथ तथा ग्राम खंडेवला, जाटौला तथा जोड़ी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'सी' तक होगी जो कि ग्राम रामपुर, जोड़ी तथा जनौला की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'सी' से पूर्व की तरफ ग्राम जनौला की उतरी सीमा के साथ तथा ग्राम जोड़ी तथा घोषगढ़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'डी' तक होगी जो कि ग्राम जनौला, घोषगढ तथा नरहेड़ा की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'डी' से पूर्व की तरफ ग्राम नरहेड़ा की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम घोषगढ़ तथा नरहेड़ा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'ई' तक होगी जो कि ग्राम नरहेड़ा, घोषगढ़ और भौड़ा कला की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- पूर्व-बिंदु 'ई' से दक्षिण की तरफ ग्राम नरहेड़ा की पूर्व सीमा के साथ तथा ग्राम भौड़ाकला तथा ऊँचा माजरा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'एफ' तक होगी जो कि ग्राम नरहेड़ा, ऊँचा माजरा तथा बाँस पदम्का की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'एफ' से पश्चिम की तरफ ग्राम नरहेड़ा की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम बाँस पदम्का, बिड़ खुर्द की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'जी' तक जो कि ग्राम नरहेड़ा, बिड खुर्द तथा नगरपालिका, पटौदी की राजस्व सीमाओं का त्रि- मिलन है।
- बिंदु 'जी' से दक्षिण की तरफ नगरपालिका, पटौदी की पूर्व सीमा के साथ तथा ग्राम बिड खुर्द तथा बास पदम्का की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'एच' तक जो कि नगरपालिका पटौदी, ग्राम बाँस पदम्का तथा मुमताजपुर की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- दक्षिण-बिंदु 'एच' से पश्चिम उतर की तरफ नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम मुमताजपुर तथा लोहाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'आई' तक जो कि नगरपालिका पटौदी, ग्राम लोहाका तथा हेड़ाहेड़ी की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'आई' से दक्षिण की तरफ ग्राम हेड़ाहेड़ी के पूर्व-दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम लोहाका, मुमताजपुर तथा हांसाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'जे' तक जोकि ग्राम हेड़ाहेड़ी, खानपुर तथा हांसाका की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'जे' से दक्षिण-पश्चिम की तरफ ग्राम खानपुर की पूर्व-पश्चिम सीमाओं के साथ तथा ग्राम हांसाका, नानूकलां, गोरियावास तथा खोड़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'के' तक जो कि ग्राम हेड़ाहेड़ी, खानपुर तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- पश्चिम-बिंदु 'के' से पश्चिम की ओर ग्राम हेड़ाहेड़ी तथा नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमाओं के साथ ग्राम खोड़ की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिंदु 'एल' तक जो कि नगरपालिका, पटौदी, ग्राम छावन तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'एल' से पश्चिम की तरफ ग्राम छावन के दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम खोड़ तथा रणसिका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'एम' तक जो कि ग्राम छावन रणसिका तथा मिलकपुर की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'एम' से उतर की तरफ ग्राम मिलकपुर की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम रणसिका, इंछापुरी तथा शाहपुरजाट की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'एन' तक जो कि ग्राम मिलकपुर, शाहपुरजाट तथा नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।
- बिंदु 'एन' से उत्तर की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम शाहपुरजाट, मुजफरा, राजपुरा, लुहारी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिंदु 'ए' तक जो कि प्रारंभिक बिंदु है।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंग्का सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया 'मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट' के निर्माण का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन की उपस्थिति में गुरुग्राम में स्वीडन के इंग्का सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया 'मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट' का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- लगभग 3500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत तथा इस क्षेत्र के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक विश्वस्तरीय रिटेल एवं लेज़र गंतव्य होगा। इससे निवेश के साथ-साथ रोज़गार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में आइकिया जो भी बेचता है, उसका 27 प्रतिशत वह स्थानीय स्रोतों से लेता है, जिसे आने वाले वर्षों में 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। इस तरह की पहल जहाँ एक ओर स्थानीय युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाएँगी, वहीं दूसरी ओर इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार व्यवस्था में 'एक्ट' अर्थात् अकांटेबिलिटी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है। इन उद्देश्यों को पाने के लिये प्रभावी और सतत् संवाद, जल्द निर्णय लेने के लिये मंथन और वर्तमान व्यवस्था में डिजिटल सिस्टम स्थापित करके पारदर्शी प्रणाली विकसित की गई है।
- आइकिया इंडिया की सीईओ सुसान पल्वरर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अपने व्यवसाय द्वारा लोगों, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने के लिये हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। इंग्का सेंटर्स के साथ हम होम फर्निशिंग बाज़ार में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे और लोगों को रिटेल का बेजोड़ अनुभव प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किफायती, खूबसूरत, बेहतरीन डिज़ाइन वाले सतत् होम फर्निशिंग उत्पाद व सेवाएँ उपलब्ध करवाएँगे।
- इस प्रोजेक्ट में इंग्का सेंटर्स 400 मिलियन पाउंड, अर्थात् 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यहाँ पर बेहतरीन रिटेल, वर्कस्पेस और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिये स्पेस होंगे। प्रोजेक्ट से लगभग 2500 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की सरसों की दो उन्नत किस्में

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की दो नई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों का हरियाणा के साथ पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और जम्मू राज्यों के किसानों को भी लाभ होगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय के तिलहन वैज्ञानिकों की टीम ने सरसों की आरएच 1424 व आरएच 1706 दो नई किस्में विकसित की हैं।
- इन किस्मों की अधिक उपज और बेहतर तेल गुणवत्ता के कारण राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर (राजस्थान) में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सरसों) की हुई बैठक में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और जम्मू राज्यों में खेती के लिए पहचान की गई है।
- उन्होंने बताया कि आरएच 1424 किस्म इन राज्यों में समय पर बुवाई और बारानी परिस्थितियों में खेती के लिये, जबकि आरएच 1706 जोकि एक मूल्यवर्द्धित किस्म है, इन राज्यों के सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई के लिये बहुत उपयुक्त किस्म पाई गई है। ये किस्में उपरोक्त सरसों उगाने वाले राज्यों की उत्पादकता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा पिछले कई वर्षों से सरसों की फसल की उत्पादकता के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर है। यह इस विश्वविद्यालय में सरसों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास और किसानों द्वारा उन्नत तकनीकों को अपनाने के कारण संभव हुआ है।
- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश में सरसों अनुसंधान में अग्रणी केंद्र है और अब तक यहाँ अच्छी उपज क्षमता वाली सरसों की कुल 21 किस्मों को विकसित किया गया है। हाल ही में यहाँ विकसित सरसों की किस्म आरएच 725 कई सरसों उगाने वाले राज्यों के किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है।

नोट :

हथनीकुंड डैम प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

18 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महत्त्वाकांक्षी हथनीकुंड डैम परियोजना की हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग को समक्ष भेजने की मंज़ूरी दी। जल आयोग के अतिरिक्त यह रिपोर्ट पाँच राज्यों में भी भेजी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में यह रिपोर्ट बेहद अहम है। हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया है।
- इस डैम का कैचमेंट एरिया लगभग 11,170 स्क्वायर किमी. होगा। इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि पानी की आपूर्ति भी होगी। हथिनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 एमयू होगी।
- यह डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजा जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हथनीकुंड डैम के बनने से आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी और इससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। डैम के बनने से बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी।
- इस डैम के बनने का फायदा रेणुका, किसाऊ और लखवार, तीनों डैम को मिलेगा। इन तीनों डैम का बैलेंसिंग रिजरवायर फंक्शन हथनीकुंड डैम को बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि डैम बिजली और पानी की आपूर्ति तो करेगा ही, साथ ही इसे पर्यटन का केंद्र भी बनाया जाएगा। कोई भी डैम पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होता है।

हालसा अध्यक्ष ने किया रेवाड़ी के एडीआर सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने 'न्याय सबके लिये' उद्देश्य की सार्थकता के साथ रेवाड़ी ज़िला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र के नए भवन का विधिवत् लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह व उच्च न्यायालय में सेशन डिविजन रेवाड़ी के प्रशासनिक जज जस्टिस मनोज बजाज ने हरियाणा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के विशेष अभियान 'गरिमा के साथ वृद्धावस्था (एजिंग विद डिग्निटी)' का शुभारंभ किया तथा बुजुर्गों के अधिकार पोस्टर का विमोचन किया।
- हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से जनमानस को अपने मामलों का निपटारा करने का एक सार्थक विकल्प मिलेगा। हरियाणा में ज़िलास्तर पर यह चौदहवाँ वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का भवन है। अलग वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के मामले में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है।
- उन्होंने 'गरिमा के साथ वृद्धावस्था (एजिंग विद डिग्निटी)' अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में यह एक सराहनीय पहल है।

नोट :

- जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि एडीआर सेंटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से परिवादियों को सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय मिलेगा, जिससे उनके धन व समय, दोनों की बचत होगी। पारिवारिक विवाद के कारण लोग लंबित लड़ाई कोर्ट में लड़ने के उपरांत समझौता करते हैं, एडीआर सेंटर ऐसे लोगों के लिये कारगर साबित होता है।
- उन्होंने कहा कि विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार के कारण अब लोक अदालतों व एडीआर सेंटर के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रति वर्ष प्रदेश के लाखों लंबित केसों का निपटान किया जा रहा है। समाज के गरीब वर्ग, महिलाओं और ज़रूरतमंदों को न्याय दिलवाने में भी विधिक सेवा काफी लाभदायक साबित रही है।

हैफेड ने लॉन्च किया मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन

चर्चा में क्यों ?

22 अगस्त, 2022 को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) ने अपने उपभोक्ता उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करते हुए मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- हैफेड ब्रांड में लॉन्च किये गए उत्पादों में मल्टीग्रेन आटा, बिस्किट की पाँच अलग-अलग किस्में, यानी जीरा, नारियल, आटा-गुड़-सौंफ, नान-खटाई और ड्राई फ्रूट बिस्कुट शामिल हैं। अन्य उत्पादों में छह अलग-अलग प्रकार के नमकीन नामत: पंजाबी तड़का, गुजराती-मिक्स, खट्टा-मीठा, बीकानेरी भुंजिया, मूंगफली पकौड़ा और लहसुन पकौड़ा शामिल हैं।
- हैफेड ने 'मैसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स'के माध्यम से हैफेड ब्रांड में बिस्कुट और नमकीन उत्पादों के निर्माण और पैकिंग के लिये हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (एचडीडीसीएफ) के साथ गठबंधन किया है (जिसकी प्रमुख हिस्सेदारी हल्दीराम दिल्ली द्वारा ली गई है)।
- इसी तरह, हैफेड ने हैफेड ब्रांड में मल्टीग्रेन आटा के निर्माण और पैकिंग के लिये एक एजेंसी को शामिल किया है। मल्टीग्रेन आटे की मुख्य सामग्री में चना, रागी, जौ, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, ओट्स, साइलियम हस्क और श्यामा तुलसी शामिल हैं।
- मल्टीग्रेन आटे की लगभग दस सामग्रियों का अनूठा संयोजन स्वास्थ्य, पाचन और मानव शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिये बहुत फायदेमंद है। हैफेड अपने मौजूदा नेटवर्क हैफेड आउटलेट्स, वितरकों और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से नए लॉन्च किये गए उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देगा।
- इस अवसर पर हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि हैफेड ने अपनी बिक्री को बढ़ावा देने और मौजूदा प्रतिस्पर्धी बाज़ार में अपने ग्राहक-आधार को व्यापक बनाने के लिये पहल की है। यह बाज़ार में अपने उपभोक्ता उत्पादों के माध्यम से फेडरेशन की समग्र उपस्थिति को और अधिक मज़बूत करेगा।

फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल 'अमृता अस्पताल' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल 'अमृता अस्पताल'का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहाँ उपचार की सुविधा मिलेगी।
- इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज थे, जो अब 13 हो गए हैं। आने वाले समय में इस कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। प्रदेश में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा। वहीं प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुँच जाएगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि माँ अमृता आनंदमयी 'अम्मा'द्वारा निर्मित यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अस्पताल में 534 आईसीयू बेड सहित 2600 बेड होंगे और इसे 81 विशेष विभागों से लैस किया जाना है, जो कि भारत में सर्वाधिक है।
- अस्पताल में 64 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा यहाँ 150 सीटों वाला पूरी तरह से आवासीय एमबीबीएस कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। एक नर्सिंग कॉलेज और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के लिये एक कॉलेज भी होगा। यहाँ रक्त और अन्य महत्त्वपूर्ण नमूनों के प्रसंस्करण के लिये देश में सबसे बड़ी, पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट लैब होगी।

हरियाणा की अंजू दहिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें हरियाणा की प्राध्यापिका अंजू दहिया का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- अंजू दहिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित होने वाली प्रदेश से एकमात्र प्राध्यापिका हैं। सोनीपत ज़िले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़वासनी में रसायन शास्त्र विषय की प्राध्यापिका अंजू दहिया ने विषय को आसान बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।
- उन्होंने रसायन शास्त्र विषय को खेल व कविता जैसी गतिविधियों से आसान बना दिया है। विद्यार्थी गतिविधियों से विषय को समझकर लंबे समय तक याद रख पाते हैं। उन्होंने रसायन शास्त्र विषय को कविता व खेल गतिविधियों में बाँटा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाकर बच्चों को भाग लेने के लिये प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने खेल गतिविधियों से सीखा, जो उन्हें याद रहता था। इससे उन्हें विषय आसान लगने लगा।
- प्राध्यापिका अंजू दहिया ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विदेश में भी प्रचार-प्रसार किया है। उन्होंने उज़्बेकिस्तान में 15 दिन तक रहकर वहाँ के लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्रेरित किया। शोध-पत्र भी प्रस्तुत किये। वहाँ उन्होंने लोगों को बताया कि बच्चों को खेल-खेल व अन्य गतिविधियों से कैसे पढ़ाया जाए।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

पुस्तक 'द गुरु: गुरुनानक की साखियाँ' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2022 को हरियाणा कैडर की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रजनी सेखरी सिब्बल द्वारा लिखित पुस्तक 'द गुरु: गुरु नानक की साखियाँ'का चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विमोचन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- यह पुस्तक श्री गुरुनानक देव जी के जीवन के बारे में साखियों के संग्रह पर आधारित है। रजनी सेखरी सिब्बल ने इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी की दस साखियाँ लिखी हैं।

नोट :

- इस पुस्तक में बटाला, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी को बाबा जी कहा है।
- यह पुस्तक 500 साल पुराने उपाख्यानों का एक संग्रह है: एक जिज्ञासु बच्चा, जिसने अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाया; एक बोधगम्य किशोर, जिसने एक तर्कहीन दुनिया में तर्कसंगत रूप से सोचा; एक जागरूक नौजवान, जिसने मौजूदा मानदंडों और रीति-रिवाज़ों के पीछे तर्क की तलाश की; एक बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्ण इंसान, जिसने समाज में गहरी जड़ें जमाने वाले पूर्वाग्रहों को मिटाने की कोशिश की और एक सौम्य, शांत तथा शुद्ध आत्मा, जो सद्भाव, शांति और करुणा का प्रसार करती है।

नीरज चोपड़ा ने जीता लुसाने डायमंड लीग का खिताब

चर्चा में क्यों ?

26 अगस्त, 2022 को हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 08 मीटर थ्रो करके लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया।

प्रमुख बिंदु

- पानीपत के गाँव खंडारा के निवासी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीट में शीर्ष स्थान हासिल कर लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए।
- इस जीत के साथ ही उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में 7-8 सितंबर को होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है, साथ ही 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिये भी क्वालीफाई किया है, जिसका क्वालिफिकेशन मार्क 20 मीटर है।
- इस साल की शुरुआत में स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 94 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भाला फेंककर दूसरे स्थान पर रहे थे।
- गौरतलब है कि हाल ही में नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मैच में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। वह अंजू बॉबी जॉर्ज (2003) के बाद ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और हरियाणा के बीच हुआ समझौता

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन पर विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी की उपस्थिति में विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडेय ने और भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि एवं कंट्री-डायरेक्टर बिशोव पराजुली ने हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देना है। इससे डब्ल्यूएफपी और हरियाणा राज्य के बीच की जाने वाली रणनीतिक पहलों के लिये आपसी समझ और दोस्ती में सुधार होगा तथा आपसी संबंधों को मज़बूती मिलेगी।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री-डायरेक्टर बिशोव पराजुली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा कि यह समझौता विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा सरकार के बीच पहले से पायलट के तौर पर चल रहे 'स्वचालित अनाज वितरण मशीन एवं 'अन्नपूर्ति कार्यक्रम'पर आधारित है।
- उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से हमारा लक्ष्य अन्य गतिविधियों के अलावा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों को क्रॉस लर्निंग के लिये एक साथ लाना भी है।
- विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और सतत् विकास लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साझेदारी के माध्यम से डब्ल्यूएफपी की वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।

नोट :

- उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार डब्ल्यूएफपी के साथ सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के कार्यान्वयन, वित्तीय और सामाजिक समावेश सहित महिला सशक्तीकरण, जलवायु अनुकूलन और लचीली खाद्य प्रणाली जैसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनमें साझा रूप से आगे बढ़ा जा सके।
- इस कोऑपरेशन-फ्रेमवर्क के तहत, डब्ल्यूएफपी तकनीकी सहायता प्रदान करके मौजूदा क्षमताओं को मज़बूत करने और मौजूदा प्रणालियों को ठोस रूप से बनाने के लिये ज्ञान, कौशल एवं विशेषज्ञता के हस्तांतरण तथा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। इस साझेदारी की अवधि पाँच वर्ष की होगी।

हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड-2021 की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड-2021 की घोषणा की। अध्यापक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य सरकार द्वारा कुल 47 अध्यापकों को यह अवार्ड दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्टेट टीचर अवार्ड -2021 के लिये चयनित कुल 47 अध्यापकों में 4 प्रिंसिपल, एक हाई स्कूल का हेड मास्टर, 13 पीजीटी, चार मौलिक स्कूल के हेड मास्टर, दो संस्कृत, तीन हिन्दी, दो ड्राइंग, एक साइंस, दो सामाजिक अध्ययन, एक डीपीई, दो प्राइमरी हेड मास्टर तथा 12 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक शामिल हैं।
- इन अध्यापकों में रेवाड़ी ज़िले से सर्वाधिक 10 अध्यापकों के नाम शामिल हैं, दूसरे नंबर पर 7 अध्यापकों के साथ भिवानी ज़िला है। इसके अलावा सोनीपत ज़िले से 6 अध्यापक, झज्जर और करनाल ज़िले से 4-4 अध्यापक, हिसार, फतेहाबाद व कुरुक्षेत्र ज़िले से 3-3 अध्यापक, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ ज़िले से 2-2 अध्यापक तथा कैथल, पानीपत और चरखी-दादरी ज़िले से 1-1 अध्यापक शामिल हैं।
- अवार्ड के रूप में प्रत्येक अवार्डी अध्यापक को एक लाख रुपए का नकद ईनाम, एक सिल्वर मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक शॉल तथा भविष्य की सर्विस के लिये महँगाई-भत्ता सहित दो एडवांस इंक्रीमेंट दी जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष राज्य स्तर पर स्टेट टीचर अवार्ड की घोषणा की जाती है। चयन प्रक्रिया मेरिट बेस पर आधारित होती है।

नोट :